



दिल्ली यात्रा के बाद पटना  
लौटे नीतीश बोले सब...

# देशबंधु

नई दिल्ली, शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024

वर्ष-16

अंक - 305

पृष्ठ - 10

मूल्य - 3.00 रुपए

02:

हंगामे के बीच दिल्ली नगर निगम का 16 हजार...  
केंद्र सरकार ने नया आरक्षण बिल लाकर गुर्जर...

03:

अप्रैल से चलेंगी पहली मानसखण्ड एक्सप्रेस...  
जांच से क्यों भाज रहे अरविंद केजरीवाल : अनुराग ठाकुर

08:

इम्ग्रोवाइज़ फिल्म पर काम  
करना एक कलाकार ...

10

सार संक्षेप

दस हजार 523  
मेंगाहटर्ज स्पेक्ट्रम की  
नीलामी को मंजूरी

नई दिल्ली।  
सरकार ने  
दूरसंचार सेवाओं  
और करोड़े की गुणवत्ता में  
सुधार के उद्देश्य से विभिन्न  
मेंगाहटर्ज स्पेक्ट्रम नीलामी को आज  
मंजूरी दी, जिससे सरकार  
को आरक्षण मूल्य पर  
9.631 लाख 7.65 कोड रुपए  
का राजस्व लिने का  
अनुमति है। धैर्यनमत्री नें देश  
मात्री की अधिकारी में केंद्रीय  
मंत्रिमंडल की बैठक में इस  
आशय के प्रस्ताव को आरक्षण  
दी गई। सूचना एवं प्रसारण  
मंत्री अनुराग शिंह ठाकुर ने  
यह जानकारी दी।

अवैध अतिक्रमण  
को हटाने को लेकर  
हल्दानी में तनाव

हल्दानी।  
उत्तराखण्ड के  
मुख्यमंत्री पुष्कर  
सिंह धामी ने प्रदेश की  
सरकारी जमीनों पर बने  
अवैध अतिक्रमण को हटाने  
के निर्देश दिए थे। जिसके  
बाद से ही प्रदेश में ऐसे  
अवैध अतिक्रमणों को जिगरों  
की कार्रवाई जारी है। इसी  
कानूनी में गुरुवार को हल्दानी  
के वनभूलपुरा थाना क्षेत्र के  
मलिकाना वाली जमीनों  
को तोड़ने की कार्रवाई की गई।  
इससे आक्रमणीय होकर वर्ता  
के लोगों ने पुलिस टीम पर  
पथराव शुरू कर दिया।

12 को एनडीए का  
हिस्सा होंगे जयंत  
चौधरी: राजभर

लखनऊ।  
राष्ट्रीय लोकदल  
(रालौद) के  
राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबंधन  
(एनडीए) में शामिल होने की  
चाही के बीच सुभासपा के  
अवैध अतिक्रमणों को आरक्षण  
ने बड़ा बयान दिया है।  
उन्होंने कहा कि 12 फरवरी  
का जयंत चौधरी एनडीए के  
साथ आ जाएगा। राजभर ने  
प्रकारों से बातचीत में यह  
बात कही।

मणिपुर की टीम ने  
आदिवासियों के लिए  
अलग प्रशासन मांगा

नई दिल्ली। 'जो  
यूनाइटेड' के  
बैठक तले  
मणिपुर के आदिवासियों के  
एक प्रतिनिधिमंडल ने  
पूर्वोत्तर के मामलों को लेकर  
गृह मंत्रालय के सलाहकार  
ए.के. मिश्रा के नेतृत्व में गृह  
मंत्रालय के अधिकारियों के  
साथ अन्य अप्रकाशित बातों  
को बताया है। इसके बाद नीतीश  
की बैठक में आदिवासी  
नेताओं ने आदिवासियों के  
लिए एक अलग प्रशासन  
बनाने और मणिपुर के शेष  
दिल्ली में सशस्त्र बल  
(विशेष शक्तियां) अधिनियम  
(एएएसपीए) लागू करने  
की मांग दी है।

भारत, फ्रांस में  
समुद्री सहयोग  
बढ़ाने पर सहमति

नई दिल्ली। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने समुद्री क्षेत्र  
में सहयोग और परस्य  
संचालन बढ़ाने पर सहमति  
द्वारा दी गई है। दोनों  
नौसेनाओं के अधिकारियों  
की बैठक में आदिवासी  
नेताओं ने आदिवासियों के  
लिए एक अलग प्रशासन  
बनाने और मणिपुर के शेष  
दिल्ली में सशस्त्र बल  
(विशेष शक्तियां) अधिनियम  
(एएएसपीए) लागू करने  
की मांग दी है।

पत्र नहीं मित्र



भाजपा और कांग्रेस के बीच पेपर युद्ध थम्ह हुआ

## मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाई कांग्रेस

■ दस साल, अन्याय काल दिया गया नाम

■ सरकार की विफलताओं को बताने का प्रयास

■ विधायिकों को तोड़कर कांग्रेस सरकारे गिराई गई



■ आज देश में लोकतंत्र खतरे की हालत में दिख रहा है।  
पिछले 10 वर्षों के दौरान भाजपा ने 411 विधायिकों को  
अपने पाल में कर लिया : मलिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अव्यक्त

नक्षर करने की कोशिश में लगे हुए हैं।

खड़गे ने कहाकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी विफलताएं छिपाने में लगे हुए हैं मार हम जनता के बीच उनकी विफलताओं को उजागर करेंगे। खड़गे ने कहाकि आज हम केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं ही क्योंकि वे हमेशा सदाचार में अपनी कामयाकी की बात खबरे हैं और अपनी विफलताएं बताते हैं। जब उनकी विफलताओं पर चर्चा होती है तो वे इसके लिए तैयार रहते हैं।

उन्होंने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे की हालत में दिख रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान भाजपा ने 411 विधायिकों को अपने पाल में कर लिया। विधायिकों को तोड़कर कर्क विफलताओं को उजागर करने के लिए नक्षर करने की कोशिश में लगे हुए हैं।

खड़गे ने कहाकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी विफलताएं छिपाने में लगे हुए हैं मार हम जनता के बीच उनकी विफलताओं को उजागर करेंगे। खड़गे ने कहाकि आज हम केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं ही क्योंकि वे हमेशा सदाचार में अपनी कामयाकी की बात खबरे हैं और अपनी वि�फलताएं बताते हैं। जब उनकी विफलताओं पर चर्चा होती है तो वे इसके लिए तैयार रहते हैं।

उन्होंने कहा कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

■ दुर्घटना के बाद दो अधिकारियों को किया गया निलंबित  
■ गृहक प्राप्तियों के लिए 25 लाख रुपए अनुग्रह दिया गी

में कही है। इस दुर्घटना के बाद दो अधिकारियों को भी निलंबित करते हैं। उनकी विफलताओं को उजागर करेंगे। खड़गे ने कहा कि आज हम केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं ही क्योंकि वे हमेशा सदाचार में अपनी कामयाकी की बात खबरे हैं और अपनी विफलताओं को उजागर करते हैं। जब उनकी विफलताओं पर चर्चा होती है तो वे इसके लिए तैयार रहते हैं।

उन्होंने कहा कि केरल के बाद दो अधिकारियों को भी निलंबित करते हैं। उनकी विफलताओं को उजागर करेंगे। खड़गे ने कहा कि आज हम केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाई कर रहे हैं ही क्योंकि वे हमेशा सदाचार में अपनी कामयाकी की बात खबरे हैं और अपनी विफलताओं को उजागर करते हैं। जब उनकी विफलताओं पर चर्चा होती है तो वे इसके लिए तैयार रहते हैं।

## गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का हिस्सा ढहने से व्यक्ति की मौत

■ नई दिल्ली के बीच उनकी विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ गृहक प्राप्तियों के लिए 25 लाख रुपए अनुग्रह दिया गी

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की विफलताओं को उजागर करते गये हैं।

■ नीतीश की व



















सर्वाधिक बढ़ने वाले शेयर	
एम्बीआई	3.54 प्रतिशत
पार्किंग	3.08 प्रतिशत
टीसीएस	1.28 प्रतिशत
एस्टोल ट्रेक	1.21 प्रतिशत
भारती एयरटेल	0.71 प्रतिशत

  

सर्वाधिक बढ़ने वाले शेयर	
आईटीसी	4.04 प्रतिशत
कॉटक बैंक	3.53 प्रतिशत
आईटीआईआई बैंक	3.34 प्रतिशत
एम्बीसी बैंक	3.03 प्रतिशत
नेस्ले इंडिया	3.02 प्रतिशत

सरफा	
सोना (प्रति दस ग्राम) स्टैर्डर्ड	47,310
गिरु	47,320
गिनी (प्रति आठ ग्राम)	31,400
चादी (प्रति किलो) टंच लैजिर	70,096
वायरा	70,183
चादी सिक्का लिंगारी	870
विकाली	880

**मुद्रा विनियम**

मुद्रा	ब्रॉड	विवर
अमेरिकी चैंबर	67.77	78.57
पौंड स्ट्रिंग	90.94	105.45
यूरो	76.54	88.78
यैन युआन	08.24	13.38

**अनाज**

देसी गेहूँ एम्पी	2400-3000
गेहूँ दद	2750-2850
आटा	2800-2900
मैदा	2900-2950
चौकर	2000-2100

**मोटा अनाज**

बाजरा	1300-1305
मसाला	1350-1500
ज्वार	3100-3200
जी	1430-1440
काबूली चना	3500-4000

**शुगर**

चीनी एस	3590-3690
चीनी एम	4150-4250
मिल डिलीपी	3470-3570
गुड़	4600-4700

**दाल-दलहन**

चना	5500-5600
दाल चना	6500-6600
मसूर काली	7350-7450
उड़द चना	10000-10100
मूंग चना	9550-9650
अरहर चना	12500-12600

**खाद्य तेलों में टिकाव, चीनी-गुड़ सरता**

# अर्थ जगत्

## धोखाधड़ी से बचाने को ईपीएस की बढ़ेंगी सुरक्षा

मुंबई 8 फरवरी (एजेंसियां)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) के जरिये लेनदेन के दौरान ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए ईपीएस की सुरक्षा बढ़ाने का नियम लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को चालू वितर्व की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) संचालित ईपीएस के ग्राहकों को डिजिटल भुगतान लेनदेन करने में संबंध बनाती है।

वर्ष 2023 में 37 करोड़ से अधिक ग्राहकों ने ईपीएस के माध्यम से लेनदेन किया। यह वितर्व समाचारशाल में ईपीएस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भारिका को और आरबीआई गवर्नर करता है। प्री दास ने बताया कि ईपीएस के लिए धोखाधड़ी से बचाने के लिए बैंकों को जाने वाली ईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य अंनबोडिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का अधिकार अनिवार्य अंनबोडिंग टेक्नोलॉजीज के द्वारा दिए गए उपयोग का उत्तराधिकारी है। इसके तहत अतिरिक्त धोखाधड़ी को बढ़ाव दिया जाएगा। इस संबंध में शोध द्वारा निर्भाव दर्शाया गया है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के साथ हाल के लिए एपीएस के अधिकारित भुगतान की सुरक्षा को बढ़ाव दिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को चालू वितर्व की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब गवर्नर 2024 में रिजर्व बैंक ने अपने द्वारा विनियमित वितर्व उपकरणों में लेनदेन के उद्देश्य से ईटीपी के लिए एक नियामक ढांचा बैतायर किया था। इसका उद्देश्य पारदर्शी बैंकों के साथ अप्रभावित भुगतान लेनदेन के लिए एक नियामक ढांचा बैतायर किया गया है। श्री दास ने कहा कि प्रौद्योगिकी को मैट्रिक्स बैंकों में नवाचारों के साथ हाल के वर्षों में वैकल्पिक प्रणालीकरण तंत्र उभरे हैं। प्री दास ने बताया कि उपयोग के लिए वैकल्पिक सुरक्षा के लिए बैंकों के उपयोग को रोकना है। इस ढांचे के तहत पांच ऑपरेटरों द्वारा संचालित तरह ईटीपी को अधिकृत किया गया है। श्री दास ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अपराधीय वाजारों के साथ अॉनलाइन उपयोग के लिए एक नियामक ढांचे की निर्माण करने का नियम लिया गया है। संशोधित नियामक ढांचा सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अलग से जारी किया जाएगा।



श्री दास ने कहा कि प्रौद्योगिकी को मैट्रिक्स बैंकों में नवाचारों के साथ हाल के वर्षों में वैकल्पिक प्रणालीकरण तंत्र उभरे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को चालू वितर्व की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब गवर्नर 2024 में रिजर्व बैंक ने अपने द्वारा विनियमित वितर्व उपकरणों में लेनदेन के उद्देश्य से ईटीपी के लिए एक नियामक ढांचा बैतायर किया था। इसका उद्देश्य पारदर्शी बैंकों के साथ अप्रभावित भुगतान लेनदेन के लिए एपीएस पर एक नियमित उपयोग की अपवाहन करने के लिए एपीएस एपीएस बैंक के वितर्व नहीं है। इस ढांचे के लिए एक नियामक ढांचा बैतायर किया गया है। श्री दास ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अपराधीय वाजारों के साथ अॉनलाइन उपयोग के लिए एक नियामक ढांचे की निर्माण लिया गया है। संशोधित नियामक ढांचा सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अलग से जारी किया जाएगा।

ईटीपी के नियामक ढांचे की होनी सनीश : आरबीआई मुंबई 08 फरवरी (एजेंसियां)। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को चालू वितर्व की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब गवर्नर 2024 में रिजर्व बैंक ने अपने द्वारा विनियमित वितर्व उपकरणों में लेनदेन के उद्देश्य से ईटीपी के लिए एक नियामक ढांचा बैतायर किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को चालू वितर्व की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब गवर्नर 2024 में रिजर्व बैंक ने अपने द्वारा विनियमित वितर्व उपकरणों में लेनदेन के उद्देश्य से ईटीपी के लिए एक नियामक ढांचा बैतायर किया गया है। श्री दास ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अपराधीय वाजारों के साथ अॉनलाइन उपयोग के लिए एक नियामक ढांचे की निर्माण लिया गया है। संशोधित नियामक ढांचा सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए एपीएस पर एक नियमित उपयोग की अपवाहन करने के लिए एपीएस एपीएस बैंक के वितर्व नहीं है। इस ढांचे के लिए एपीएस पर एक नियमित उपयोग की अपवाहन करने के लिए एपीएस एपीएस बैंक के वितर्व नहीं है। इस ढांचे के लिए एपीएस पर एक नियमित उपयोग की अपवाहन करने के लिए एपीएस एपीएस बैंक के वितर्व नहीं है। इस ढांचे के लिए एपीएस पर एक नियमित उपयोग की अपवाहन करने क

